राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा गठित श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों के समक्ष 30-6-90 तक लंबित पड़े औद्योगिक विवादों और आवेदनों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

एक वर्ष तक	एक से दो वर्षों के मध्य	दो से तीन वर्षों के मध्य	तीन वर्षों से ज्यादा	कुल
72,321	43,546	33,664	43,359	1,92,890 *

* इन आंकड़ों में बिहार राज्य शामिल नहीं है ।

283. [Transferred to the 4th March, 1991]

भारी उद्योग विभाग द्वारा उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति

284. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 1991 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "33 डी. एच. ए.ई. यूनिट्स में नोट एचीव आउटपुट टार्गेट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारी उद्योग विभाग के उद्योगों के लिए वर्तमान वर्ष के लिये उत्पादन के कुछ लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो ये निर्धारित लक्ष्य क्या-क्या थे और दिसम्बर, 1990 के अंत तक इन एककों द्वारा कुल कितना उत्पादन किया गया ; और

(घ) क्या उत्पादन की वर्तमान गति को देखते हुए निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है ; यदि नहीं, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के 33 निर्माणकारी उपक्रमों ने अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान अन्तिम रूप से 5057 करोड़ रु. का उत्पादन प्राप्त किया है जबकि इस अवधि के लिए 5895 करोड़ रुपये का उत्पादन लक्ष्य रखा गया था ।

(घ) 33 एककों द्वारा पूरे वर्ष 1990-91 के दौरान 8384 करोड़ रुपये का उत्पादन प्राप्त करने की आशा है जो 8616 करोड़ रुपये के लक्ष्य का लगभग 97% होगा और वर्ष 1989-90 के दौरान प्राप्त उत्पादन से लगभग 12% अधिक होगा ।

Acquiring of Asiasat channel and cable TV network

285. SHRI S. MADHAVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem published in the Times of India dated 5-1-91 under the caption "Move to acquire Asiasat Channels"; if so, what steps are being taken to safeguard our interests;

(b) what are the steps taken to prevent the private businessmen from running any of the channels on Asiasat;

(c) what steps are taken by Govern-jnent to prevent private T.V. companies located in on offshore place from plan ning their programme to India;

(d) whether the inter-departmental committee set up to study the various as pects of setting up of cable T.V, networks